Shri Hari Vishnu Kamath: To the continuance of prohibition.

Shri Hathi: If I may say so, the States are not opposed to the policy of prohibition as such....

Shri Hari Vishnu Kamath: They want money.

Shri Hathi: The reason for their reluctance in implementing the policy is this. They say that the revenues of the State will suffer and they will lose. This is the argument. But basically they are not opposed. If we pay them the money then they are for prohibition.

Shri K. D. Malaviya: Was not this aspect of the question considered previously when this basic question was decided?

Mr. Speaker: I cannot allow a second supplementary question by the hon. Member.

Shri S. M. Banerjee: May I know whether it is a fact that the Cabinet at the Centre is horribly divided on this issue, and if so, what percentage is for prohibition and what percentage is against it, and who are leading in both the groups?

Mr. Speaker: I am not allowing that question.

Shri S. M. Banerjee: How can you disallow this question? On what grounds have you disallowed this?

Mr. Speaker: I need not say on what grounds.

Shri S. M. Banerjee: Can I not ask whether the Cabinet is divided on this issue or not?

Mr. Speaker: I cannot allow that question.

Shri S. M. Banerjee: That amounts to protecting the Cabinet.

Mr. Speaker: That also has to be done.

Shri U. M. Trivedi: Shri Kamath has been pleased to remark that this was a big farcical fraud. Is it not a fact that prohibition and corruption are linked with each other? On account of the growing of corruption, has not prohibition become a nullity now?

Shri Hathi: I cannot say whether prohibition and corruption are linked together. One cannot say that the man who does not drink is not corrupt or that the man who drinks is corrupt. We cannot have a link between the two. Both the things are independent of each other. I would not like to connect the two.

I do not think it is correct to say also that it is a fraud. If we say that a man should not take wine lest he should lose his senses, there is no fraud in it.

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का समय

+

*571. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के समय में परिवर्तन किया जा रहा है ;

(ख) क्या कार्यालयों का समय पहले की तरह दस बजे प्रातः से पांच बजे तक किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). वर्तमान काम के घंटों में, जो आपातकालीन स्थिति की घोषणा पर निर्धारित किए गए थे, परिवर्तन के प्रश्न पर आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब सरकार यह जानती है कि आधुनिक और हम से ज्यादा ठंडे देशों में सरकार का काम काज आठ बजे और 9 बजे शुरू हो जाता है, और रूस, अमरीका और जरमनी में बीच के खाने के समय को छोड़ कर कहीं आठ घंटे कहीं सात घंटे काम होता है, तो क्या कारण है कि यहां पर काम के घंटे इतने कम हैं, और क्या बस वगैरह की कमी, आने जाने की गड़बड़ी, राशन खरीदने की गडबड़ी आदि के कारण जो घंटे बरबाद होते हैं वे भी एक कारण हैं । ?

श्री ल० ना० मिश्र : यदि माननीय सदस्य काम के घंटे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे तो हम इसका हार्दिक स्वागत करेंगे । लेकिन मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य का सरकारी कर्मचारियों से सम्पर्क बहुत कम है । यहां तो आन्दोलन कुछ और ही चल रहा है, लोग काम के घंटों को घटवाना चाहते हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इसके इतिहास को देखें कि कितनी मुश्किल से हम वर्तमान घंटों को चला रहे हैं और किस तरह से चला रहे हैं । दूसरी जगह 9 बजे से काम शुरू होता है और यहां पर हम पौने दस बजे से चलाते है, लेकिन यह भी बड़ी कठिनाई के साथ और समझौते के बल पर ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर आप कहें तो मैं दूसरा सवाल कर लूं । वैसे मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा ही सवाल कर लीजिए ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सरकारी नौकरों के दिन भर में यह सरकार चार से छः घंटे बस वगैरह की कमी और राशन आदि खरीदने की गड़बड़ी में बिगाड़ती है और इसलिए देश का भी और सरकारी नौकरों का भी समय बरबाद करती है । उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह तो सत्य है कि जितनी सुविधाएं दूसरे देशों में हैं उतनी यहां नहीं हैं । ट्रांसपोर्ट की भी कमी है और राशन की दुकानों की भी कमी है, यह सही है । लेकिन इसमें चार और छः घंटे लगते हैं और दफ्तर में आठ घंटे लगते हैं यह बात भी अतिरंजित है । लेकिन उनका समय इन चीजों में लगता है और मैं बताउं कि सरकारी नौकरों को सुविधा देने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट के टाइमिंग्स को बदला है और दिल्ली में जो 17 या 18 कोआपरेटिव स्टोर थे उनकी संख्या बढ़ा कर 29 या 30 तक ले गये हैं, और भी सुविधायें देने की कोशिश की है, और इससे उनकी बड़ी भलाई हुई है ।

श्री मधु लिमये : सामाजिक परिस्थिति कारण है, जाति व्यवस्था आदि कारण हैं, उनको लेकर आज कारखानों में काम करने वाले, मेहनत करने वाले मजदूर और दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी, उनके काम के जो घंटे हैं, सेवा की जो शर्त है, छुट्टियां और तनख्वाह आदि में काफी फर्क है । तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह फर्क दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सवाल तो इसमें आता नहीं । यह तो काम के घंटों का सवाल है । लेकिन मैं माननीय सदस्य का ध्यान सैकिंड पे कमीशन की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं, उसको देखें कि हमने इस मसले को सुलझाने के लिए क्या किया है और किस हद तक उसमें सफल हुए हैं । लेकिन इसमें तो यह सवाल तनख्वाह का नहीं आता ।

श्री बागड़ी : जरमनी में सरकारी कर्मचारी नौ घंटे काम करते हैं और अमरीका में आठ घंटे और भारत के मजदूर भी आठ घंटे काम करते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि उन मुल्कों के मुकाबले में और अपने देश के मजदूरों के मुकाबले में यहां के सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटों को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने कहा कि माननीय सदस्य काम के घंटे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकें तो हम उसका स्वागत करेंगे ।हमारे एस. एम. बनर्जी तो काम के घंटे कम करवाना चाहते हैं और कर्मचारियों के आन्दोलन का समर्थन करते हैं । हमने इसके लिए बड़ी कोशिश की और भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भी इसके लिए आदेश दिया था और उन्होंने बात की, और स्वाराज्य से पहले जो सप्ताह में साढ़े 33 घंटे का काम था और उसको साढ़े चालीस घंटे तक ले आए हैं । यदि आप ज्यादा लाना चाहते हैं तो आप के सुझाव का हम स्वागत करते हैं,आप हम को इस काम में मदद कीजिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि संकट-काल में काम के घंटों में जो आधा घंटा बढ़ाया गया था, कान्ट्रोवर्टरी हैल्थ स्कीम एडवाईजरी कमेटी ने उसको खत्म कर दिया है, यदि हां, तो सरकार ने जो आधा घंटा बढ़ाया है, क्या वह उसको जाड़े के महीनों में कम कर देगी, क्योंकि इस आधे घंटे में काम ज्यादा नहीं होता है, बल्कि बातें ही होती हैं, ताकि कर्मचारी जाड़े के महीनों में जल्दी पहुंच सकें और काम के बाद बाजार कर सकें ?

श्री ल० ना० मिश्र : हम को कहा जाता है कि काम के घंटे बढ़ाने चाहिए, जब कि माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको घटा देना चाहिए ।

Shri S. M. Banerjee: Longer hours do not give you more efficiency.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जवाब सुनें । अगर यह आधा घंटा कम कर दिया जाये, तो क्या बातें कम हो जायेंगी, या बाकी वक्त में से आधा घंटा बातें होंगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारे पास यह मांग नहीं आई है कि समय घंटा दिया जाये, बल्कि हमारे सामने यह मांग हुई है कि हम समय बढ़ा दें ।

श्री स० मो० बनर्जी : जाड़े के महीनों में घटा दें ।

श्री ल० ना० मिश्र : स्टाफ के कौंसिल में इस बात को एग्जामिन किया गया था, इस पर विचार किया गया था,हम लोगों के साथ बैठे थे । शायद माननीय सदस्य को पता होगा कि पहले टाईम सवा दस बजे सुबह था जिस को पौने दस बजे कर दिया गया है और शाम को सवा छः बजे से पौने छः बजे कर दिया गया है । गवर्नमेंट इस टाईम को जाड़े के मौसम में पहले के टाईम से अच्छा समझती है और हम इस को चलाना चाहते हैं ।

Mr. Speaker: Next question. Shri B. K. Das.

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order. May A request you that in view of the urgent public, even national, importance of the matter, if the House is agreeable, you will be pleased to take up Question No. 578 on Sant Fateh Singh's Talks with P. M. and the Home Minister?

Mr. Speaker: No. I will proceed according to the order.

Shri Kapur Singh: I would like to support the hon. Member because this is a very important question. It is a very reasonable request. There are so many Members who are like-minded.

Shri Hari Vishnu Kamath: I said if the House was agreeable.

Shri Buta Singh: I also support it.

Mr. Speaker: Shri B. K. Das may put his question.

Schemes for Rehabilitation of Migrants

\+

***573. Shri B. K. Das:**
Shri P. R. Chakraverti:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether any industrial or agricultural schemes have been started